के. कानन न्यायमूर्ति के समक्ष ।

मेसर्स पीएमआई, इंडस्ट्रीज लिमिटेड - याचिकाकर्ता

बनाम.

ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण और . अन्य - उत्तरदाता

2010 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 58.

1 जनवरी, 2010.

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002-एस.17-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226- डीआरटी कंपनी द्वारा दायर समीक्षा आवेदन में कंपनी को अपने कब्जे को बनाए रखने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में 28 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देता है - कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करती है - अपीलीय न्यायाधिकरण अपने कब्जे को बनाए रखने के लिए भुगतान करने का निर्देश देता है - यह निर्णय ऋण वसूली न्यायाधिकरण को करना था।इक्विटी पर - ऐसे मामले में जहां याचिकाकर्ता का दावा है कि पूरी कार्यवाही कानूनी रूप से दूषित है, 28 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश एक कठोर और एक लंबा आदेश हो सकता है - समीक्षा आवेदन में उठाए गए तर्कों पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा दिया जाने वाला अंतिम निर्णय - अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों को रद्द कर

दिया गया और धारा 17 की सख्त सीमाओं के भीतर विवाद की जांच के लिए मामले को डीआरटी को भेज दिया गया।

अभिनिर्धारित किया कि एक कंपनी जो 13.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए भी संसाधन जुटाने में असमर्थ है, उसे अपने कब्जे को बनाए रखने और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा आवेदन पर मुकदमा चलाने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में 28 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना वास्तव में एक लंबा आदेश था। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या ऋण वसूली न्यायाधिकरण समीक्षा आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम था और क्या उसने पक्षकारों को निपटान करने और कब्जे के खिलाफ राहत प्रदान करने का निर्देश देने में अपनी सीमा का उल्लंघन किया था। समीक्षा के लिए एक आवेदन 'कानून में संभव' था और याचिका पर विचार करना और पार्टियों को निपटारे के लिए समय देना शायद अवैध नहीं था, हालांकि पार्टियों को समझौते के लिए धकेलना अनुचित था, अगर वे इच्छुक नहीं थे। इसलिए अपीलीय न्यायाधिकरण को केवल इस मामले को तत्काल निपटान के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण को वापस भेजना चाहिए था, बिना समस्याओं को और बढ़ाया बिना और इसके कब्जे को बनाए रखने के लिए और अधिक भुगतान करने के निर्देश दिए जाने चाहिए थे।. यह ऋण वसूली न्यायाधिकरण को इक्विटी पर फैसला करना था जब उसके पास निपटान के लिए एक समीक्षा आवेदन

था। देनदार कंपनी टीथर के अंत में है; इसे या तो यह दिखाना होगा कि धारा 13 (2) के तहत नोटिस और लेनदार द्वारा लिए गए कब्जे से संबंधित आगे की कार्यवाही कानून में वैध नहीं है या पूरी तरह से विफल है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण का निर्णय 2006 के सीडब्ल्यूपी संख्या 19406 में पहले से की गई इस न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार करेगा और संबंधित पक्षों द्वारा ली गई सभी प्रासंगिक आपत्तियों पर विचार करेगा। ऐसे मामले में जहां याचिकाकर्ता का दावा है कि पूरी कार्यवाही कानूनी रूप से प्रभावित है, 28 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देना एक कठोर और लंबा आदेश हो सकता है। याचिकाकर्ता ने अभी तक केवल 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, लेकिन भविष्य में इसका खुद का आचरण निर्धारित करेगा कि यह जीवित रह सकता है या नहीं। समीक्षा आवेदन में उठाए गए तर्कों पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले अंतिम निर्णय से एक नया अध्याय खुल जाएगा या बिलकुल बंद हो जाएगा । (Para 5)

अश्विनी चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता,

वकील शैब्या सूद के साथ याचिकाकर्ता की ओर से

कंवलजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुमीत गोयल, एडवोकेट, कैविएटर-प्रतिवादी नंबर 2 के लिए

निर्णय

के कानन , न्यायमूर्ति ।

. (1) ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत कार्यवाही में पारित अपने निर्णय की समीक्षा के लिए एक आवेदन में दिए गए अंतरिम निर्देशों से व्यथित होकर, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड(जिसे बाद में एआरसीआईएल के रूप में संदर्भित किया गया है) ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में अपील को प्राथमिकता दी थी। डीआरटी के अंतरिम निर्देशों ने पक्षकारों को विवाद को हल करने की संभावना तलाशने और ऋण के पुनर्भुगतान के लिए एक योजना तैयार करने की सलाह देने के अलावा और कोई निर्देश नहीं दिया। एआरसीआईएल ऐसा कुछ नहीं चाहता था और डीआरएटी के समक्ष यह दलील देने की कोशिश की गई थी कि डीआरटी अपनी इच्छा के खिलाफ निपटान के एजेंडे को आगे बढ़ाकर अपने विवेकाधिकार की व्यापकता से परे है । इस बीच डीआरटी द्वारा कब्जा हटाने के खिलाफ उसके समक्ष कार्यवाही जारी रखने के दौरान दी गई अंतरिम रोक समाप्त हो रही थी और एआरसीआईएल द्वारा दायर अपील में, देनदार कंपनी ने रोक के लिए एक आवेदन दायर किया था,

जब अपीलीय न्यायाधिकरण ने 25 नवंबर, 2009 के अंतरिम आदेश द्वारा कब्जे के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश दिया और अंतरिम उपाय के रूप में 28 करोड़ रुपये का भुगतान एक वर्ष के भीतर करने का निर्देश दिया। विशेष समय पर मामले की सुनवाई 25 जनवरी, 2010 को करने का निर्देश दिया। 28 करोड़ रुपये के भुगतान का निर्देश देनदार कंपनी के लिए बहुत कठोर लग रहा था और इसने 2009 की सिविल रिट याचिका संख्या 18912 में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की। इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने 9 दिसम्बर, 2009 को एक आदेश पारित किया जिसमें रिट याचिका का निपटान इस निदेश के साथ किया गया कि अधिकरण के समक्ष सुनवाई 15 दिसम्बर, 2009 तक स्थगित कर दी जाए और मामले का निपटान 23 दिसम्बर, 2009 से पहले कर दिया जाए। अपीलीय अधिकरण ने 23 दिसम्बर, 2009 के अपने निर्णय के अनुसार ऐसा किया लेकिन उसने 25 नवम्बर, 2009 के अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा और कहा कि 2 करोड़ रुपए का भुगतान 29 दिसम्बर, 2009 से पहले कर दिया जाएगा और मांग नोटिस की 50% शेष राशि कब्जा बनाए रखने के लिए एक शर्त के रूप में 7 जनवरी, 2010 से पहले जमा की जानी चाहिए ऐसा निर्देश दिया। अंतिम आदेश के माध्यम से, अपीलीय न्यायाधिकरण ने पुनर्निर्माण कंपनी एआरसीआईएल

को राशि वापस लेने की स्वतंत्रता दी और ऋण वसूली न्यायाधिकरण को कानून के अनुसार मामले का निपटान करने का निर्देश दिया।

(2) इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया गया आदेश अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निपटान का अंतिम आदेश है। याचिकाकर्ता की 'शिकायत' यह है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने सचमुच याचिकाकर्ता को अपने संसाधनों से वंचित कर दिया था और कब्जा बनाए रखने के लिए एक बड़ी राशि जमा करने का निर्देश देकर अपने मुद्दे को पूर्व-निर्धारित कर रहा था, जबकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दा स्वयं अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार कार्यवाही थी। यह अवैध था और धारा 13 (4) के तहत कब्जे से संबंधित बाद की कार्यवाही और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता से कंपनी द्वारा उठाए गए दंडात्मक कदम वास्तव में याचिकाकर्ता को डराने और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय के बिंदु को अर्थहीन बनाने का एक प्रयास था।. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील के अनुसार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने मूल रूप से 31 अगस्त, 2009 को अधिनियम की धारा 17 के तहत दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अपील समय से पहले थी, 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 19406 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों और 2008 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 12989 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। 30 अगस्त,

2009 को ऋण वसूली अधिकरण के अंतिम आदेश को मूल रूप से 2009 की सिविल रिट याचिका संख्या 13853 में इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी, लेकिन बाद में देनदार कंपनी ने समीक्षा के लिए याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली और उस समीक्षा आवेदन में ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने कुछ अंतरिम निर्देश दिए थे जिन्हें अपील का विषय बनाया गया था अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष।

(3) यह देखा जा सकता है कि देनदार कंपनी वास्तव में अपने कब्जे को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, अभी भी असमर्थ है क्योंकि यह लेनदार और पुनर्निर्माण कंपनी की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती है जो उनके लिए वैध रूप से देय है। अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस में दावा 56 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा में था, लेकिन जब तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता से कब्जा लेने की मांग की गई, तब तक दावा ब्याज लोड करके 300 करोड़ रुपये की राशि तक बढ़ गया था। वर्ष 2003 ओटीएस के रूप में निर्धारित राशि थी, लेकिन देनदार कंपनी उस राशि का भी भुगतान करने में सक्षम नहीं थी और पुनर्निर्माण कंपनी जिसने ऋण को खुद को हस्तांतरित किया था, इसलिए, इसके अनुसार क्या सही था। देनदार कंपनी, जिसे

बीआईएफआर के समक्ष कार्यवाही के लंबित होने से लंबे समय तक रोक लगी थी, ने कभी भी अपने लाभ के लिए राहत का उपयोग नहीं किया, बल्कि केवल धोखाधड़ी कर रही थी। इसलिए, पेंडुलम के दो चरम सीमाओं में से एक शामिल था, देनदार कंपनी जो अपने कब्जे को बनाए रखने की इच्छा रखती है, भले ही वह इन सभी वर्षों के लिए राशि का भुगतान करने में असमर्थ हो, उसने घोषित स्थिति घोषित की कि वह एक बीमार कंपनी थी और जब पुनर्वास योजना काम नहीं करती थी। अपने चरित्र चित्रण में, पुनर्निर्माण कंपनी ने कंपनी के पुनर्निर्माण का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन कबाड़ के अंतिम टुकड़े की तलाश कर रहा था, एक कंपनी की अंतिम सांस को दावत देने की कोशिश कर रहा था जैसा कि एक भूखा गिद्ध करेगा। दूसरी ओर पेंडुलम की एक ओर पुनर्निर्माण कंपनी का मुखर आक्रोश है कि वह किसी भी पर्याप्त राशि की वसूली करने में असमर्थ है, हालांकि इसने वित्तीय संस्थानों के क्रेडिट का हस्तांतरण प्राप्त कर लिया था और 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 19406 में एक समय इस न्यायालय की अनुकूल टिप्पणियां प्राप्त करने के बावजूद उचित रूप से जो कुछ भी उचित है, उसे लेने के लिए पर्याप्त रूप से लंबा इंतजार किया है, जब इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों में सुरक्षित

लेनदारों को शामिल करने में अपनाई गई देरी की रणनीति पर नाराजगी जताई।

इस न्यायालय की खंडपीठ ने देनदार कंपनी द्वारा उठाए गए तर्क को भी दूर कर दिया कि धारा 13 (2) या अधिनियम के तहत नोटिस सक्षम नहीं था। जब यह बताया गया कि पुनर्निर्माण कंपनी के पास मूल्य में कुल सुरक्षित ऋण का 33% था और अधिनियम की धारा 13 (9) के संदर्भ में, इसके पास आईडीबीआई की सहमति थी, जो कुल सुरक्षित ऋण का 32% हिस्सा रख रहा था और SBI-I जो कुल ऋण का 34% था। डिवीजन बेंच ने कहा कि पुनर्निर्माण कंपनी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए आगे बढ़ने की हकदार थी और याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा पुनर्निर्माण कंपनी के खिलाफ लागू किए गए एस्टोपेल के सिद्धांत उसके बचाव में नहीं आएंगे।

(4) यदि खंड पीठ का निर्णय पार्टियों के बीच सभी कानूनी विवादों को खत्म करना था, तो शायद कानून ने अपना काम किया होगा जब पुनर्निर्माण कंपनी ने परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए आगे बढ़ना होगा, लेकिन खंड पीठ ने अभी भी राहत प्रदान की और देनदार कंपनी को अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई करने की स्वतंत्रता देकर विकल्पों को बंद नहीं करना चाहता था। यदि नोटिस और कब्जे के मुद्दे को धारा 17 के तहत अपील के

माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, तो अनिवार्य रूप से ऋण वसूली न्यायाधिकरण निर्णय देने के लिए बाध्य था। यदि उसने मूल रूप से यह कहकर इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लेने का विकल्प चुना था कि यह असामयिक था, तो यह निश्चित रूप से इस न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन कर रहा था, जिसे बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा पुष्टि की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में पुन यह निदेश नहीं दिया गया कि संपत्ति को देनदार कंपनी के हाथों से तत्काल बेदखल किया जाना चाहिए। इसने ऋण वसूली न्यायाधिकरण को कब्जे के मामले में उचित आदेश देने के निर्देश दिए। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने देनदार कंपनी को कुछ शर्तों पर रखने का अंतरिम आदेश भी दिया था और बाद में समीक्षा के आदेश में निर्देश दिया था कि पक्ष को निपटान का प्रयास करना चाहिए। यदि यह मुकदमेबाजी का पहला दौर होता तो यह एक सार्थक हस्तक्षेप होता। यह कई उतार-चढ़ाव से गुजरा था और रिश्ते में खटास आ गई थी, जब तक कि पार्टियों ने स्वेच्छा से ऐसा करने का फैसला नहीं किया, तब तक कुछ भी तय नहीं था। देनदार कंपनी के लिए निपटान एक मीठा शब्द था यदि केवल इसने मुकदमेबाजी को लंबा कर दिया और इसके लिए अपने कब्जे को बनाए रखना संभव बना दिया। पुनर्निर्माण कंपनी के लिए, यह कोई उपशामक नहीं था और इसे

मारने और कब्जे लेने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए एक उपकरण के रूप में था।

(5) एक कंपनी जो 13.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए भी संसाधन जुटाने में असमर्थ है, उसे अपने कब्जे को बनाए रखने और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा आवेदन पर मुकदमा चलाने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में 28 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना वास्तव में एक लंबा आदेश था। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या ऋण वसूली न्यायाधिकरण समीक्षा आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम था और क्या उसने पार्टियों को निपटान करने और कब्जे के खिलाफ राहत प्रदान करने का निर्देश देते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था। कानून में समीक्षा के लिए एक आवेदन संभव था और याचिका पर विचार करना और पार्टियों को निपटारे के लिए समय देना शायद अवैध नहीं था, हालांकि पार्टियों को समझौते के लिए धक्का देना अनुचित था, अगर वे इच्छुक नहीं थे। इसलिए अपीलीय न्यायाधिकरण को केवल इस मामले को तत्काल निपटान के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण को वापस भेजना चाहिए था, बिना समस्याओं को और बढ़ाया बिना ताकि इसका कब्जा बनाए रखने के लिए और अधिक भुगतान किए जा सकें। यह ऋण वसूली न्यायाधिकरण को इक्विटी पर फैसला करना

था जब उसके पास निपटान के लिए एक समीक्षा आवेदन था। देनदार कंपनी टीथर के अंत में है; इसे या तो यह दिखाना होगा कि धारा 13 (2) के तहत नोटिस और लेनदार द्वारा लिए गए कब्जे से संबंधित आगे की कार्यवाही कानून में वैध नहीं है या पूरी तरह से विफल है। ऋण वसूली अधिकरण का निर्णय 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 9406 में पहले से की गई इस न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार करेगा और संबंधित पक्षों द्वारा ली गई सभी प्रासंगिक आपत्तियों पर विचार करेगा। ऐसे मामले में जहां याचिकाकर्ता का दावा है कि पूरी कार्यवाही कानूनी रूप से प्रभावित है, 28 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देना एक कठोर और लंबा आदेश हो सकता है। याचिकाकर्ता ने अब तक केवल 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, लेकिन भविष्य में इसका खुद का आचरण निर्धारित करेगा कि यह जीवित रह सकता है या नहीं। समीक्षा आवेदन में उठाए गए तर्कों पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले अंतिम निर्णय से एक नया अध्याय खुलेगा या बिलकुल बंद हो जाएगा।

(6) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों को निरस्त किया जाता है और इस मामले को अब ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा लिया जाएगा और अधिनियम की धारा 17 की सख्त सीमाओं

के भीतर विवादों की जांच की जाएगी। अंतिम निर्णय दिए जाने तक, देनदार कंपनी बिना किसी शर्त के अपना कब्जा बनाए रखेगी। रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, लेकिन परिस्थितियों में, जहां पुनर्निर्माण कंपनी को निर्णय की अंतिम प्रक्रिया में देरी होती है कि क्या वह कब्जा ले सकती है या नहीं, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को लागत 25,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी